मुख्य समाचारः–

- प्रदेश में स्थानांतरण नीति तथा नए जिलों के गठन की घोषणा से लोगों की आपत्तियों को देखते हुए मंत्रिमण्डल ने पुनर्गठन आयोगों की स्थापना की घोषणा की।
- प्रदेश में देशी और विदेशी पर्यटकों की आवाजाही को बढ़ाने के लिये मूलभूत सुविधाओं का विस्तार करने पर जोर दिया जाएगा।
- केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश ने कहा कि सभी राज्यों का मनरेगा का लेखा–जोखा इस साल नवम्बर में संसद में प्रस्तुत किया जाएगा।
- गंगा में हो रहे अवैध खनन को लेकर हरिद्वार जिला प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई शुरु कर दी है।

मंत्रिमण्डल–बैठक

मुख्य सचिव आलोक कुमार जैन ने मंत्रिमण्डल की बैठक के बाद आज पत्रकारों से वार्ता में बताया कि विगत सरकार द्वारा की गई स्थानांतरण नीति तथा नए जिलों के गठन की घोषणा से लोगों की आपत्तियों को देखते हुए मंत्रिमण्डल ने इस संबंध में पुनर्गठन आयोगों की स्थापना की घोषणा की है। उन्होंने बताया कि मंत्रिमण्डल ने अब सरकारी क्षेत्रों में आउट सोर्सिंग के आधार पर कार्य करने वालों के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग की सीटों का आरक्षण किया जाएगा। कैबिनेट ने यह भी निर्णय गया कि अब निजी विश्वविद्यालय खोलते समय विश्वविद्यालयों को अपने शैक्षणिक स्टाफ, पाठ्यक्रम व अन्य जानकारियां अपने विज्ञापनों तथा वेबसाइट पर जारी करनी होगी। मंत्रिमण्डल ने वैट पर कम से कम लगने वाले साढ़े चार प्रतिशत कर को बढ़ाकर पांच प्रतिशत करने का निर्णय लिया है। मुख्य सचिव ने यह भी बताया कि आगामी विधानसभा सत्र में राज्य में वित्तीय क्षेत्र में पारदर्शिता लाने के लिए बिल प्रस्तुत किया जाएगा। कैबिनेट ने प्रदेश के सीमान्त और पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए पचास करोड़ रुपए की विकास निधि की स्वीकृति दी है, जिससे प्रदेश के चौहत्तर ब्लॉक में मूलभूत सुविधाओं को बढ़ावा दिया जाएगा। मुख्य सचिव ने बताया कि प्रदेश में स्थायी निवास और जाति प्रमाण पत्र के विवाद को देखते हुए कैबिनेट ने एक सब कमेटी बनाने का निर्णय भी लिया है।

पर्यटन

प्रदेश में देशी और विदेशी पर्यटकों की आवाजाही को बढ़ाने के लिये मूलभूत सुविधाओं का विस्तार करने पर जोर दिया जाएगा। यह बात विधानभवन में पर्यटन मंत्री अमृता रावत ने प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित विभागीय बैठक में कही। पर्यटन मंत्री ने कहा कि रिवर राफ्टिंग एवं बीच कैम्पिंग के लिये उत्तराखण्ड की परिस्थितियों के अनुरूप अलग से नीति बने। उन्होंने इसके लिए प्रारूप प्रस्तुत करने में गोवा, लद्दाख, सिक्किम, हिमांचल की नीतियों का अध्ययन करने को कहा है। उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड में सामान्य, धार्मिक, ऐतिहासिक, खोजपूर्ण और साहसिक पर्यटन की अपार संभावनाऐं एवं उपयुक्त वातावरण मौजूद हैं। साथ ही जल, आकाश, बर्फ से संबंधित विभिन्न पर्यटनोपयोगी खेलों के लिये भी यहां उपयुक्त वातावरण मौजूद है। श्रीमती रावत ने ग्रामीण पर्यटन परियोजनाओं और ईको टूरिज्म को बढावा देने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि वन एवं पर्यटन विभाग मिलकर पर्यटन को बढाने के लिये कार्य करें।

रैन बसेरे

पर्यटन मंत्री अमृता रावत ने प्रदेश में रैन बसेरों का स्थलीय निरीक्षण कर इनके नियमित संचालन की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। आज देहरादून में आयोजित बैठक में उन्होंने बताया कि राज्य में चौतींस रैन बसेरों का निर्माण किया गया है, जिन्हें विभाग द्वारा संचालित होना दिखाया गया है, लेकिन अनेक रैन बसेरे वर्षों से बन्द पड़े हैं, जिसका लाभ पर्यटकों को नहीं मिल पा रहा है। श्रीमती रावत ने कहा कि पौड़ी जिले कें नीलकंठ और चमोली जिले के गोविन्दघाट में रैन बसेरों के निर्माण के लिए लाखों रुपए की धनराशि स्वीकृत की गई है, किन्तु अभी तक इन रैन बसेरों का निर्माण कार्य पूरा नहीं हो पाया है। उन्होंने अवशेष निर्माण कार्यों को पूरा करने के निर्देश दिए हैं।

टिहरी बांध

टिहरी के जिलाधिकारी डा. रंजीत सिन्हा ने टिहरी बांध की झील के आरएल आठ सौ तीस के दायरे में रह रहे एक सौ छियासठ परिवारों को वहां से हटाने के निर्देश दिए हैं। नई टिहरी में आयोजित बैठक में उन्होंने इस महीने की इकतीस तारीख तक प्रभावितों के भवन आदि के भुगतान के भी निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि आने वाले समय में बांध की झील का जल स्तर बढ़ने से यहां रह रहे लोगों को खतरा पैदा होने की संभावना है, जिसे देखते हुए प्रभावित लोगों को वहां से हटाने के निर्देश दिए गए हैं।

मुलाकात

उत्तराखण्ड क्रांति दल के अध्यक्ष त्रिवेन्द्र सिंह पंवार ने आगामी दो अक्टूबर को गैरसैंण में आयोजित होने वाली कैबिनेट की बैठक का स्वागत किया। मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा से मुलाकात में श्री पंवार ने कहा कि सरकार के इस निर्णय से गैरसैण में विकास के नये आयाम स्थापित होंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार गैरसैण के विकास के लिए प्रतिबद्ध है और इससे पर्वतीय जनपदों का भी विकास होगा। उधर, श्रीनगर क्षेत्र की विभिन्न मांगों को लेकर नगर पालिका परिशद श्रीनगर के अध्यक्ष मोहन लाल जैन ने भी मुख्यमंत्री से मुलाकात की, जिसपर मुख्यमंत्री ने उनकी मांगों पर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिये।

केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री

केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश ने कहा कि सभी राज्यों का मनरेगा का लेखा–जोखा इस साल नवम्बर में संसद में प्रस्तुत किया जाएगा। उन्होंने बताया कि वर्ष 2007 से 2011 तक की अवधि को इसमें शामिल किया गया है। उन्होंने बताया कि सभी ग्राम पंचायतों को मनरेगा का लेखा–जोखा इस साल से नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा जिला स्तर पर नियुक्त किए गए चार्टर्ड एकाउन्टेंट द्वारा प्रमाणित होना अनिवार्य होगा। कुछ राज्यों में ग्रामीण रोजगार योजना में व्याप्त भ्रष्टाचार का जिक्र करते हुए श्री रमेश ने कहा कि इसे दूर करने के लिए केन्द्र बहुत अधिक कुछ नहीं कर सकता, भ्रष्टाचार से लड़ाई का प्रमुख दायित्व राज्य सरकारों विशेषकर ग्राम पंचायतों पर है। उन्होंने बताया कि मनरेगा में यदि कोई अनियमितताएं होती हैं तो इससे संबंधित सूचना केन्द्रीय दल द्वारा राज्य सरकारों को उसे ठीक करने के लिए दी जाती है। यह जानकारी केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री ने राज्य सभा में एक प्रश्न के उत्तर में दी है। उन्होंने बताया कि सभी राज्यों में लेखा–परीक्षा का काम इस समय जारी है और उनके मंत्रालय को इसकी रिपोर्ट अक्तूबर के अंत तक मिल जाएगी।

अवैध खनन–कार्रवाई

गंगा में हो रहे अवैध खनन को लेकर हरिद्वार जिला प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई शुरु कर दी है। जिलाधिकारी सचिन कुर्वे के निर्देश पर हरिद्वार में अब तक आधा दर्जन से ज्यादा अवैध रूप से चल रहे स्टोन क्रेशरों एवं दर्जनों ट्रेक्टर–ट्रॉलियों को सीज कर दिया गया है। लम्बे समय से प्रभावी कार्रवाई न होने के कारण लोगों में अवैध खनन को लेकर आक्रोश था। हमारे प्रतिनिधि ने बताया कि प्रदेश में सत्ता बदलने के बाद कांग्रेस की सरकार अवैध खनन के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है, जिसके तहत प्रदेश के पूर्व राजस्व मंत्री दिवाकर भट्ट के स्टोन–क्रेशर को भी सीज कर दिया गया है। पूर्व में उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय ने अवैध खनन को लेकर सख्त रुख अपनाते हुए सरकार से इस संबंध में खनन नीति दोबारा बनाने के निर्देश भी जारी किए थे। हरिद्वार में अवैध खनन को रोकने के लिए साधु–सन्त एवं पर्यावरणविद् आन्दोलन करते रहे हैं।

मास्टर प्लान

नैनीताल झील प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्रों में महायोजना के कम में मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा। कुमाऊं आयुक्त हेमलता ढौंढियाल की अध्यक्षता में आयोजित प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में शीघ्र ही मास्टर प्लान बनाए जाने का निर्णय लिया गया है। बैठक में महायोजना के लिए भवन निर्माण उपविधि में संशोधन की बात भी कही गई। बैठक में श्रीमती ढौंढियाल ने भवन निर्माण से संबंधित चौबीस लम्बित मामलों में से बारह का निस्तारण किया। इसके अलावा तीन अन्य मामलों को निरस्त भी किया गया। बैठक में दो प्रकरणों की पुनः जांच के आदेश दिए गए, जबकि तीन प्रकरणों को शासन को भेजने का फैसला लिया गया।

बदरीनाथ–रुद्रनाथ

चमोली जिले में स्थित बदरीनाथ धाम के कपाट खुलने के बाद से अब एक लाख चालीस हजार से अधिक श्रद्धालु भगवान बदरीविशाल के दर्शन कर चुके हैं। बदरीनाथ–केदारनाथ मंदिर समिति के मुख्य कार्याधिकारी बीडी सिंह ने बताया कि पिछले दो सप्ताह में यहां पहुंचे श्रद्धालुओं के चढ़ावे से मंदिर समिति को डेढ़ करोड़ रुपए की आय हुई है। उन्होंने कहा कि बदरीनाथ धाम में शुरु की गई टोकन व्यवस्था से श्रद्धालुओं को भगवान के दर्शन करने में सुविधा हो रही है। उधर, चमोली जिले में स्थित पंच केदारों में से एक भगवान रुद्रनाथ के कपाट खुलने की प्रकिया शुरु हो गई है। बीते दिन भगवान रुद्रनाथ की डोली को श्रद्धालुओं के दर्शनों के लिए गोपेश्वर स्थित गोपीनाथ मंदिर परिसर में रखा गया। इस बीच, आज गोपेश्वर में पूजा अर्चना के बाद डोली को पनार के लिए रवाना किया गया। हमारे प्रतिनिधि ने बताया कि रुद्रनाथ मंदिर के कपाट आगामी शुकवार को विधि–विधान और पूजा अर्चना के साथ प्रातः पांच बजे श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए खोल दिए जाएंगे।

अल्पसंख्यक

मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने कहा है कि राज्य सरकार अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए विभिन्न योजनाएं शुरू कर रही है, जिसके लिए अलग से मंत्रालय का गठन किया गया है। देहरादून में आयोजित एक कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अल्पसंख्यक समुदाय को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए विभिन्न योजनाएं शुरू की जा रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा दे रही है, ताकि स्थानीय लोगों को रोजगार के अधिक से अधिक अवसर मिले।